

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 22, सोमवार, शाके 1945-जून 12, 2023 <i>Jyaistha 22, Monday, Saka 1945- June 12, 2023</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।

वन विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, मई 17, 2023

संख्या 2(12)वन\2023 :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियाँ हैं या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार हैं या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार हैं,

और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती हैं,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती हैं कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं० 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती हैं और ऐसी जाँच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6,7,8,10,11 (2), 12,13,14,17,18 एवं 19 में प्रवाहित हैं।

और इस अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जाँच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected) वन के रूप में घोषित करती हैं, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तिथि से आरक्षित (Reserved) हो जावेंगे और

पूर्वोक्त तारिख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार वन उपज का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
शिखर अग्रवाल,
अति. मुख्य सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि एवं बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची(आरक्षित वृक्ष)

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा न.	क्षेत्रफल (हैक्टर)	भूमि किस्म
1	ठाडीबेरी	झाडोल	उदयपुर	उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम	बिलानाम भूमि एवं अन्य खातेदार सीमा ग्राम बीछीवाडा	ठाडीबेरी	341/79	20.375	पहाड
					सीमा ग्राम सेमला एवं अन्य खातेदार			20.375	
					सीमा ग्राम आमोड				

शांतिलाल मेघवाल,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
फलासिया।

मुकेश सैनी,
उप वन, संरक्षक,
उदयपुर।

द्वितीय अनुसूची
पेड़ों की सूची
ठाडीबेरी

क्र.सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1.	Butea monosperma (Lamk.) Taub	खाखरा
2.	Wrightia tinctoria (Roxb.) R.Br.	खिरनी
3.	Lannea coromandelica (Houtt.) Merrill	गोदल
4.	Terminalia Belerica, Roxb	बहेडा
5.	Madhuca indica	महुआ
6.	Sapindus Mukorossi	अरीठा
7.	Cassia Fistula linn	अमलतास

शांतिलाल मेघवाल,
क्षेत्रीय वन अधिकारी
फलासिया।

मुकेश सैनी,
उप वन, संरक्षक,
उदयपुर।

प्रमाण पत्र

वन खण्ड - ठाडीबेरी
 रेंज - रेंज फलासिया
 वन मण्डल - उप वन संरक्षक, उदयपुर

- 1- प्रारूप में दर्शाई गई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 ई (उदयपुर-कुण्डाल - नयाखेडा-झाडोल-फलासिया -सोम-खोखरा-अम्बावेली) सड़क कार्य में आ रही 79.4710 हैक्टेयर वन भूमि के बदले में प्राप्त हुई गैर वन भूमि है। कुल प्रभावित 79.4710 हैक्टेयर वन भूमि में से 59.1140 हैक्टेयर भूमि ग्राम करगेट तहसील गिरवा में पूर्व में वन विभाग को दी गई थी शेष 20.3750 हैक्टेयर भूमि ग्राम ठाडीबेरी की की बिलानाम गैरकाबिल काश्त किश्म पहाड आ.न. 79 रकबा 24.0600 हैक्टेयर में से इस कार्यालय को प्राप्त हुई जिसकी प्रकृति राजस्व जमाबन्दी में राजकीय वन विभाग के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर वन विभाग द्वारा वानिकीय विकास कार्य करवाये गये हैं तथा यह क्षेत्र वर्तमान में वन विभाग के नाम अमलदरामद है।
- 2- विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है, प्रस्तावित भूमि में प्रथम दृष्टतया कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं किये हुए है।
- 3- प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र पूर्व से ही विभाग के अधीन है, जिन पर वानिकीय विकास कार्य किये गये हैं एवं भविष्य में किये जाने की सम्भावना है।
- 4- प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य खाखरा, खिरनी, बहेडा, महुवा, अरीठा, गोदल व अमलतास प्रजातियों के पेड एवं झाड़ियां हैं।
- 5- प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक हैं एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग हो रहा है।
- 6- प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है।
- 7- पूर्व में खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात् नये प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे हैं।
- 8- इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

शांतिलाल मेघवाल,
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 फलासिया।

मुकेश सैनी,
 उप वन, संरक्षक,
 उदयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।